भारत सरकार

भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2075

07 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन के लिए कच्चा माल

2075. श्री सुशील कुमार गुप्ता:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और गैर-कोकिंग कोल, प्राकृतिक गैस आदि जैसी कच्ची सामग्रियों की प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई नए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर नई इस्पात नीति, 2017 के अनुरूप तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्पात उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (ग): स्वदेशी इस्पात उद्योग की मौजूदा मांग/खपत को पूरा करने के लिए देश में लौह अयस्क एवं गैर-कोकिंग कोल के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। तथापि, कोकिंग कोल का आयात किया जाता है चूंकि देश में उच्च- गुणवत्तापूर्ण कोयले/कोकिंग कोल (निम्न राख कोयला) की आपूर्ति मांग की तुलना में सीमित है जिसका उपयोग मुख्यतया एकीकृत इस्पात उत्पादकों द्वारा किया जाता है। इस्पात निर्माण में प्रयोग में आने वाली कच्ची सामग्री की कीमतें बाजार पर आधारित हैं।

सरकार ने खनिजों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खनन एवं खनिज नीति सुधार शामिल हैं ताकि अधिक उत्पादन, लीज

समाप्त हो चुकी खदानों की जल्दी नीलामी एवं प्रचालन, व्यापार में सरलता, सभी वैध अधिकारों एवं अनुमोदनों के निर्बाध अंतरण, खनन प्रचालनों एवं आपूर्ति को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने, खनन पट्टों के हस्तांतरण, कैप्टिव खदानों को उनके खनिज उत्पादन के 50 प्रतिशत तक की बिक्री की अनुमति प्रदान करने, गवेषणा गतिविधियों को बढ़ाना सुनिश्चित किया जा सके।

कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में लगाए गए अनुमान के अनुसार कोकिंग कोयले की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2022 में मिशन कोकिंग कोल की शुरूआत की है। कोकिंग कोल के आयात को कम करने के उद्देश्य से इस्पात उद्योग द्वारा कोकिंग कोल की ब्लेंडिंग को मौजूदा 10-12% से बढ़ाकर 30-35% कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अंतर्गत कोयला मंत्रालय द्वारा किए गए रूपांतरणकारी उपायों से वर्ष 2030 तक स्वदेशी कच्चे कोयले का उत्पादन बढ़कर 140 एमटी तथा धुलाई के बाद प्रयोग होने योग्य कोकिंग कोयले की उपलब्धता लगभग 48 एमटी तक होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाकर, जैव ईंधनों एवं नवीकरणीय ईंधनों को अपनाकर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाकर, रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार करके तथा मांग प्रतिस्थापन के साथ पंचमुखी रणनीति को अपनाकर एलएनजी सहित हाइड्रोकार्बन पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

****